मेथनॉल को पेट्रोल में मिलाने की योजना पर लगी रोक

नीति आयोग ने मेथनॉल पर बदली अपनी नीति, जेनरेटर, टेलीकॉम टावर और अन्य स्टेशनरी पावर यूनिट्स में जारी रहेगा इस्तेमाल

[योगिमा शर्मा | नई दिल्ली]

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर के बीच नीति आयोग ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के लिए वैकल्पिक फ्यूल के तौर पर मेथनॉल को बढ़ावा देने की योजना को रोक दिया है। इस योजना को पहले सरकार के शीर्ष अधिकारियों का भी समर्थन था। हालांकि आयोग मेथनॉल से चलने वाले जेनरेटर, टेलीकॉम टावर और अन्य स्टेशनरी पावर यूनिट्स के इस्तेमाल और कुकिंग फ्यूल में मेथनॉल मिलाने को बढ़ावा देना जारी रखेगा। इससे सभी सेक्टर्स से ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने महत्वाकांक्षी 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' का खाका खींचा था। इसके तहत उन्होंने क्रूड इंपोर्ट में 2030 तक 100 अरब डॉलर की सालाना कटौती का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कुकिंग दोनों फ्यूल में 15 पर्सेंट मेथनॉल मिलाने का सुझाव दिया था। इससे फ्यूल की कीमतों में कम से कम 10 पर्सेंट की कमी

- **वित्त वर्ष** 2020 तक देश की सड़कों पर चलने वाले सभी थ्री-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, लेकिन 150 सीसी से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक होने में वित्त वर्ष 2025 तक समय लगेगा
- **भारत में** बिकने वाले कुल व्हीकल्स का 78% हिस्सा टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स का है

आती। एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया कि अब बाकी सब चीजों को छोड़कर ई-मोबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, 'हम वैकल्पिक फ्यूल जल्द लाने की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इसमें मेथनॉल का इंपोर्ट करना और इसका स्टेशनरी पावर प्लांट्स में इस्तेमाल शामिल है।' अधिकारी के मुताबिक 15 पर्सेंट मेथनॉल मिलाने के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया, 'हमने मेथनॉल के मिश्रण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चुना है और इस मामले में सरकार की मंजूरी लेने के लिए हम

जल्द ही कैबिनेट नोट लाएंगे।' सरकार ने देश में ई-मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की FAME-II पहल के तहत 10,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार की योजना अगले सालों में 10 लाख इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स को सड़कों पर उतारने की है। इस बीच ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अगुवाई वाले उच्चस्तरीय समिति ने 31 मार्च 2023 से चरणबद्ध तरीकों से पूरी तरह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और टू-व्हीलर्स को लागू करने की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2020 तक देश की सड़कों पर चलने वाले सभी थ्री-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, लेकिन 150 सीसी से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक होने में वित्त वर्ष 2025 तक समय लगेगा। सरकार देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के हब में बदलना चाहती है। भारत में बिकने वाले कुल व्हीकल्स का 78 पर्सेंट हिस्सा टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स का है। ग्लोबल स्तर पर भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर करने वाला देश है। वह करीब 5 लाख करोड़ लीटर ऑयल इंपोर्ट करता है। देश में सालाना 2,900 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9000 करोड़ डीजल की खपत होती है। वैकल्पिक फ्यूल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ने से सरकार को ऑयल इंपोर्ट कम होने की उम्मीद है।

Economic Times
16/7/2019